ASSOCHAM IN THE NEWS

Millennium Post

10 June, 2017

British election result to increase risks for doing business: India Inc

£ dives as PM Theresa May loses majority for Conservative Party, plunging country into new uncertainty

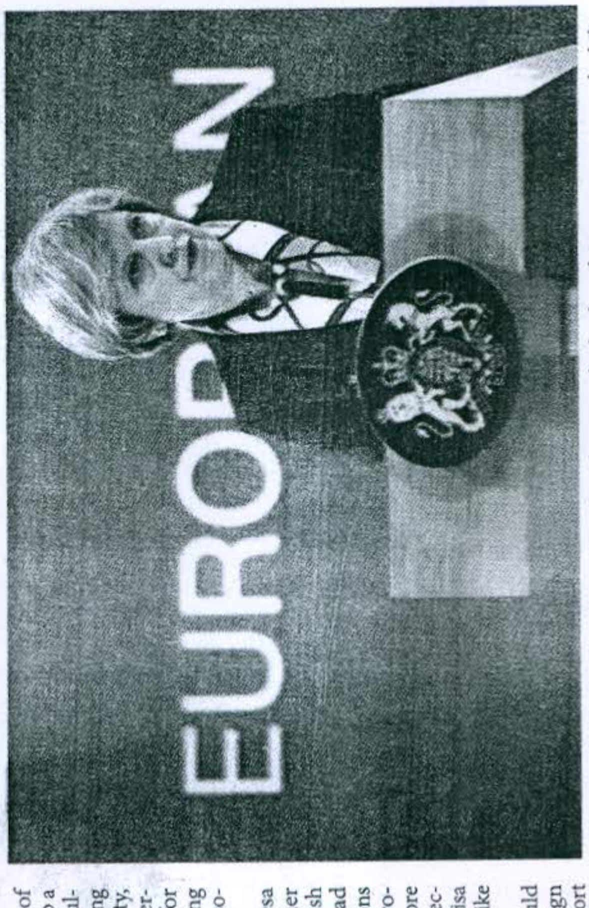

NEW DELHI: The result of UK election, which threw up a hung Parliament with the ruling Conservative party failing to muster a simple majority, will add to geopolitical uncertainty and increase risks for global businesses including India Inc, industry body Assocham said on Friday.

"Prime Minister Theresa May losing majority for her Conservative party in British Parliament, just days ahead of the scheduled negotiations on the Brexit with the European Union would mean more uncertainties for a host of sectors like financial services, visa policies, trade and services like IT.

"Besides, there would be volatility in the foreign exchange markets in the short term, at least," said Assocham Secretary General D S Rawat.

He said if one adds the outcome of the UK election to what is happening in the US and the impact being felt on the Indian businesses, mainly IT and geo-political, uncertainties are on the higher side.

May, who is now facing mounting pressure to resign, had called the polls three years ahead of schedule hoping to boost her negotiating powers during the complex Brexit talks. The Brexit talks were set to begin on June 19, but the election result - a sort of turnaround in fortunes for both major political parties - have thrown that timetable into doubt.

Meanwhile, the pound fell sharply after Britain's election saw the Conservatives lose their majority in parliament, raising questions about the next government's ability to lead the talks to leave the European Union.

The British currency lost as much as 3 cents against the dollar by Friday as the results confirmed exit poll predictions that Prime Minister Theresa May had failed in her gambit to gain a stronger majority for those Brexit talks. The pound fell as low as $1.2636 from $1.2955 on Thursday, before recovering slightly to trade at $1.2737.

Above all, investors are worried about the general uncertainty surrounding the country - whether a bruised May will resign in due course, whether the Conservatives will be able to form a new government or whether it will be an alliance of opposition parties, led by the Labour Party.

"The big picture is that political uncertainty could take weeks or months to be resolved and it is likely to weigh on both financial markets (in particular the pound) and the economy," said Paul Hollingsworth, economist at Capital Economics in London.

As the dust settles, one issue will dominate investors' concerns above all: whether Britain is more or less likely to retain privileged access to the EU's single market, the destination for most of the country's exports.

Currently, investors seem to worry that a weakened Conservative prime minister would not have the power to resist calls from some within the party who want a clean divorce from the EU, even if that means losing privileged access to the EU single market.

When May called the election in April, she did so with the Conservatives riding high in the polls, and the pound had surged on expectations that a big majority for the Conservatives would allow her to quell the so-called euroskeptics in her parliamentary ranks.

But her decision to call the general election has backfired, and it is not even certain she will remain at the helm.

Samuel Tombs, analyst at Pantheon Macroeconomics, says the pound could drop further, to 1.2600, where it was trading before May announced the election in April.

Complicating the outlook for the pound, however, is the strong showing by the Labour Party, which has advocated for closer ties between Britain and the EU single market. PTI

Pioneer (Hindi) **12 June, 2017**

यूपी की नई औद्योगिक नीति में दिया जाए एमएसएमई व एफडीआई पर खास ध्यान

एसोचैम ने कहा कि योगी सरकार को निवेशकों में नया विश्वास भरना होगा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उद्योग मण्डल 'एसोचैम' ने उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में लघु तथा मध्यम उद्योगों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने पर खास जोर दिए जाने का सुझाव देते हुए कहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को सूबे में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों में नया विश्वास भरना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पिछले दिनों मुलाकात करने आए एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया और महासचिव डी. एस. रावत ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति अत्यन्त गतिशील और प्रोत्साहक होनी चाहिए। जजोडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई का प्रतिशत मात्र 0 . 02 प्रतिशत ही है। निवेशकों को प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से ही इतनी बुरी हालत है। जब सरकार प्रोत्साहन ही नहीं देगी तो कोई यहां क्यों आएगा। वह गुजरात या महाराष्ट्र जाएगा। एसोचैम अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि उनका उद्योग मण्डल प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लिए सुझाव देने का इच्छुक है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की औद्योगिक नीति के मसविदे को विभिन्न पक्षों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे सरकारी पोर्टल पर डालने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए उद्योग मण्डलों से भी सुझाव मांगे हैं।

एसोचैम महासचिव रावत ने कहा कि उनका उद्योग मण्डल एक समिति बनाने जा रहा है। यह समिति महाराष्ट्र, गुजरात तथा कुछ दक्षिणी राज्यों की सर्वश्रेष्ठ नीतियों का गहन अध्ययन करेगी। उसके बाद 15 जुलाई तक उसके मसविदे को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। हमारी नीति का खास जोर लघु उद्योग, मंझोले उद्योग, बड़े उद्योग और एफडीआई होगा।

रावत ने कहा कि हम अनेक छोटे-छोटे सम्मेलन कर निवेशकर्ताओं को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार को निवेशकर्ताओं में विश्वास भरना होगा।

Dabang Duniya 12 June, 2017

यूपी की नई औद्योगिक नीति में दिया जाए एमएसएमई और एफडीआई पर खास ध्यान : एसोचैम

एजेंसी ✡ लखनऊ

उद्योग मंडल 'एसोचैम' ने उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में लघु तथा मध्यम उद्योगों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)आकर्षित करने पर खास जोर दिये जाने का सुझाव देते हुए कहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को सूबे में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों में नया विश्वास भरना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पिछले दिनों मुलाकात करने आये एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया और महासचिव डी.एस. रावत ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति गतिशील व प्रोत्साहक होनी चाहिए।

जजोडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई का प्रतिशत मात्र 0.02 प्रतिशत ही है। निवेशकों को प्रोत्साहन ना मिलने की वजह से ही इतनी बुरी हालत है। जब सरकार प्रोत्साहन ही नहीं देगी तो कोई यहां क्यों आएगा। वह गुजरात या महाराष्ट्र जाएगा। एसोचैम अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि उनका उद्योग मंडल प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लिये सुझाव देने का इच्छुक है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की औद्योगिक नीति के मसविदे को विभिन्न पक्षों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे सरकारी पोर्टल पर डालने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इसके लिये उद्योग मंडलों से भी सुझाव मांगे हैं।

रावत ने कहा कि उद्योग मंडल एक समिति बनाने जा रहा है। यह समिति महाराष्ट्र, गुजरात तथा कुछ दक्षिणी राज्यों की सर्वश्रेष्ठ नीतियों का गहन अध्ययन करेगी। उसके बाद 15 जुलाई तक उसके मसविदे को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। हमारी नीति का खास जोर लघु उद्योग, मंझोले उद्योग, बड़े उद्योग और एफडीआई होगा।